लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

# हरियाणा संवाद

पाक्षिक 16-30 सितंबर 2022 www.haryanasamvad.gov.in अंक -50

"युग बदलता है तो मान्यताएं बदलने लगती हैं, इस सत्य को सदैव याद रखना चाहिए

: स्वामी दयानंद

अमृत सरोवर योजना से बदल रही गांवों की तस्वीर

3

करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन

5

अध्यापक दिवस पर 93 अध्यापकों को पुरस्कार

7

# सुशासन का संकल्प

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विशेष प्रतिनिधि

## लापरवाही पर कसा जा रहा शिकंजा

राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को ईमानदार एवं पारदर्शी व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों का जीवन सहज व सरल हो इसके लिए सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं। तय समय सीमा में सेवाएं एवं सुविधाएं मयस्सर हों इसके लिए भी कर्मचारियों व अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई हैं। इसके चलते इस मार्ग में आने वाली चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जिनसे पार पाने की कोशिशें की जा रही हैं।

सरकारी कामकाज चुस्त-दुरुस्त हों तथा भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फिर भी कहीं 'तीन दो पांच' होता है तो उसके लिए सीएम का उड़न दस्ता लापरवाहों पर नकेल कसने का काम कर रहा है। विगत तीन माह में सीएम उड़न दस्ते ने विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी एवं अन्य संस्थानों पर 344 छापेमारी की।

**इन छापों में मुख्यत:** 58 मामले खाद्य पदार्थों में मिलावट, 59 मामले अवैध बार व अहाता चलाने, 34 मामले जीएसटी चोरी, 33 मामले अवैध रूप से शराब की तस्करी, 22 मामले ओवरलोड, 14 मामले अवैध माइनिंग व आठ मामले नकली बायोडीजल व पेट्रोलियम पदार्थों के पकड़े गए।

अवैध निर्माण, अवैध आरओ प्लांट, झोलाछाप डॉक्टर्स, घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, ईंट भट्ठों द्वारा प्रदूषण, हुक्का बार तथा अवैध तरीके से सरकारी राशन का स्टॉक रखने के मामलों पर भी निरन्तर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 265 मुकद्मे दर्ज हुए तथा 126 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

उड़न दस्ते द्वारा उपरोक्त अवधि में जीएसटी चोरी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के ट्रकों को राउंडअप करके टैक्स विभाग से लगभग 3,33,58,295 रुपए का जुर्माना वसूल करवाया गया। इस अवधि में बिजली चोरी पकड़ कर 17,78,660 रुपए तथा ओवरलोड वाहनों पर 71,10,913 रुपए का जुर्माना वसूल करवाया गया। इसी तरह शराब माफिया पर छापेमारी कर 189 पेटी अंग्रेजी शराब व 1525 पेटी देसी शराब तथा 357 बोतल अवैध शराब बरामद की गई ।

उड़न दस्ते द्वारा जींद में बेसिल फार्मा कंपनी पर रेड की गई, जहां बगैर लाईसैंस के 14 प्रकार की अंग्रेजी दवाई व पैकिंग मशीन बरामद की गई। यहां से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुछेक ऐसे सरकारी डाक्टरों पर रेड की गई जो निजी प्रैक्टिस कर रहे थे।

पानीपत नगर निगम कार्यालय में 61 कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे थे तथा पैंडिग कार्य व फाईलों के निरीक्षण करने पर लगभग 242 सीएम विंडो की शिकायतों की जांच लंबित पाई गई। विकास कार्यों के 49 मामलों में शुरूआती अनुमानित बजट में वृद्धि पाई गई। प्रोपर्टी आईडी बनवाने के 722 आवेदन तथा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के 62 आवेदन लंबित पाये गये ।

## संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस नेतृत्व को संगठित अपराध के खिलाफ सख्ती से पेश आने के लिए कहा है। प्रदेश में लोगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाए रखना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रदेश क्राइम शून्य होगा तो ज्यादा निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अनुकूल कानून व्यवस्था प्रदेश के विकास को गति देती है। मुख्यमंत्री ने सरकार की अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फील्ड में तैनात पुलिस अधिकारी गैंगस्टरों, बदमाशों और नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी रणनीति तैयार करते हुए इसे लागू करने पर ध्यान दें। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस को बिना किसी दबाव के कानून सम्मत होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए ताकि अपराधियों में भय पैदा हो और नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। प्रदेश में साइबर क्राइम की स्थिति को लेकर समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ अपराध के तौर-तरीकों में भी बदलाव आया है। वर्तमान में साइबर क्राइम की काफी शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने डीजीपी को आदेश दिए कि पुलिस के साइबर तंत्र को और अधिक मजबूत बनाएं ताकि साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। राज्य पुलिस की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मोस्ट वांटेड व उद्घोषित अपराधियों तथा बेल जंपर्स की गिरफ्तारी के साथ अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाएं जाएं। गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस अधिकारियों से सीएम के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा जिससे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और मजबूत हो सके।

## तनिष्का ने नीट यूजी-2022 में किया टॉप

हरियाणा की बेटियों ने हर क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है। चाहे बात खेलों की हो या शिक्षा की। अब हरियाणा ने एक और उपलब्धि हासिल की है। नारनौल के गांव मिर्जापुर बाछोड़ की तनिष्का यादव ने नीट यूजी-2022 में ऑल इंडिया रैंक - वन हासिल कर नया इतिहास रच दिया है। उसने कुल 720 अंक में से 715 अंक प्राप्त किए। हरियाणा की निशा ने भी नीट यूजी में 720 में से 705 नंबर हासिल किये हैं।

तनिष्का की दसवीं तक की पढ़ाई नारनौल के यदुवंशी शिक्षा निकेतन में हुई। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई उन्होंने राजस्थान के कोटा शहर में की। वह दो साल से कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थीं। तनिष्का पढ़ाई के लिए कोई विशेष समय नहीं निकालती थी, लेकिन उसने नीट की तैयारी दसवीं कक्षा से ही शुरू कर दी थी। उनका कहना है कि अगर पूरी लग्न व मेहनत से किसी परीक्षा की तैयारी की जाए तो सफलता पाना कोई मुश्किल नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छात्रा तनिष्का से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। उन्होंने तनिष्का के माता- पिता से भी बात की और बधाई दी।

# प्रगति का होगा मूल्यांकन

प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के मद्देनजर हर जिले की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार एक नया तंत्र विकसित करने जा रही है। जल्द ही इससे संबंधित योजना को लागू किया जाएगा, जिससे हर जिले में खण्ड एवं स्थानीय निकाय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों का मूल्यांकन हो सके।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस बारे में फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। जिला उपायुक्तों व अन्य संबद्ध विभागों के साथ भी बैठकें कर इस संबंध में सुझाव मांगे जाएं।

नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर राज्य के सभी खण्डों और शहरी स्थानीय निकायों के मध्य ऐसा तंत्र विकसित करने की कवायद शुरू होने जा रही है। इससे एक ओर जहां विकास के मामले में पीछे चल रहे खण्डों और निकायों के बारे में जानकारी मिलेगी, वहीं इनमें प्रतियोगिता की भावना भी पैदा होगी, जिससे सभी अपने क्षेत्र में बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे।

इस नई पहल से राज्य सरकार का उद्देश्य हर उस क्षेत्र की पहचान करना है, जो विकास के मामले में पीछे चल रहा है, ताकि उसे सुदृढ़ कर उसे भी विकास यात्रा में जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ध्येय शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर जोर देते हुए प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण विकास व कल्याण सुनिश्चित करना है। यह तभी संभव होगा जब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का समान विकास होगा। इसलिए इस नए तंत्र को विकसित करने पर जोर दिया गया है।

विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा खंड स्तर पर विकास कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। जो खण्ड जिस मापदंड में विकास गति में धीमे पाए जाएंगे, उनमें विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 10 मापदंड चिह्नित किए गए हैं।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा तैयार प्रारूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन मूलभूत सुविधाएं इत्यादि मापदंडों को चिह्नित किया गया है। इन मापदंडों पर शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन किया जाएगा। जिन्हें हर मापदंड के लिए अलग से स्कोर दिए जाएंगे और कुल स्कोर के आधार पर निकायों की रैंकिंग की जाएगी।

संपादकीय

## नशा मुक्ति केंद्र

नशे का प्रचलन पिछले कुछ वर्षों से पंजाब के साथ-साथ हरियाणा में भी बढ़ने लगा था। हरियाणा में नशे के प्रचलन की आशंका इस बात से बढ़ जाती थी क्योंकि सीमा पार से पंजाब और पंजाब से केंद्र की राजधानी दिल्ली की ओर नशे की घुसपैठ का मार्ग हरियाणा से होकर ही गुज़रता रहा है।

विकास के मार्ग पर हर चुनौती को गंभीरता से लेने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निदेश दिए कि प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की जरूरत पर सर्वे करवाया जाए, जिससे यह पता लग सके कि आज के समय में किस जिला में कितने नशा मुक्ति केंद्र खोलने की आवश्यकता है।

नशा समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है जिस पर तुरंत लगाम लगाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार नशे की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयासरत है।

युवा जल्दी नशे की गिरफ्त में आते हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और रेडक्रॉस सोसाइटी इत्यादि सभी हितधारकों को स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के खिलाफ जागरूक करने पर ज़ोर देना चाहिए और अधिक से अधिक जागरुकता अभियान चलाए जाने चाहिए।

सीएम ने जिलों में बने नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे महीने में एक बार अपने-अपने जिलों में बने नशा मुक्ति केंद्रों का दौरा कर वहां दी जा रही सुविधाओं का जायजा अवश्य लें।

रेडक्रॉस सोसायटी को 'जहां कम वहां हम' की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आमजन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सेवाभाव से कार्य करना चाहिए। वर्तमान में 18 वर्ष आयु तक के मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए देखभाल करने की व्यवस्था है,परंतु 18 वर्ष से ऊपर आयु के व्यक्ति यों के लिए इस प्रकार की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है। उनकी देखभाल के लिए योजना बनाए जाने की आवश्यकता है।

-डॉ. चन्द्र त्रिखा

# 'एसवाईएल' पर हरियाणा का जायज हक

एसवाईएल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें केंद्र सरकार ने कोर्ट को अवगत करवाया कि पंजाब सरकार मामले में सहयोग नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने बताया कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो इस मसले पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित कर मतभेद समाप्त करने और समाधान के लिए प्रयास करे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एसवाईएल हरियाणावासियों का हक है और वे इसे लेकर रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हरियाणा के लिए यह पानी अत्यंत आवश्यक है। एक तरफ उन्हें यह पानी नहीं मिल रहा है, जबकि दूसरी ओर दिल्ली उनसे अधिक पानी की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इस मामले में एक टाइम लाइन तय होना जरूरी है।

सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण कार्य को पूरा करना हरियाणा और पंजाब राज्यों के बीच पुराना और गंभीर मसला है। एसवाईएल नहर न बनने के कारण रावी, सतलुज और ब्यास का अधिशेष, बिना चैनल वाला पानी पाकिस्तान में चला जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एसवाईएल मुद्दे को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 18 अगस्त, 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, पंजाब आगे कार्रवाई नहीं कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से 6 मई 2022 को एक अर्ध-सरकारी पत्र केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री को भेजा गया था जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दूसरे दौर की बैठक जल्द से जल्द बुलाने का अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह को भी इस विषय में एक अर्ध-सरकारी पत्र लिखा था, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित करने की बात कही गई थी।

# आय प्रमाण पत्र के संबंध में नए दिशा-निर्देश

## विभागों को परिवार पहचान पत्र से लेनी होगी आय संबंधी जानकारी

हरियाणा सरकार ने सरल पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में जारी एक परिपत्र के अनुसार, हरियाणा का कोई भी सरकारी विभाग राज्य के किसी भी निवासी को आय संबंधी प्रमाण दस्तावेज जमा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, यदि वह परिवार पहचान संख्या (पीपीएन) प्रदान करता है और उसकी आय परिवार सूचना डाटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित के रूप में चिह्नित है।

एफआईडीआर में उपलब्ध पीपीएन से जुड़ी सत्यापित जानकारी से अब सरल पोर्टल के माध्यम से काउंटर पर आय प्रमाण पत्र जारी करना संभव हो गया है।

### आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पोर्टल

अब हरियाणा के पात्र निवासियों को सरल पोर्टल के माध्यम से पीपीएन के प्रावधानों के अनुसार आय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र अतिरिक्त उपायुक्त-सह- जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के तहत प्रमाण पत्र पर उनके प्रतिकृति हस्ताक्षर के माध्यम से जारी किए जाएंगे। पत्र में जारी निर्देशों में कहा गया है कि एफआईडीआर में निहित सत्यापित आय के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। एक व्यक्ति जो हरियाणा राज्य का निवासी है, आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।

### आय सत्यापन के लिए ऑनलाइन सेवा

एफआईडीआर में अपनी आय सत्यापित करने के इच्छुक निवासी meraparivar.haryana.gov.in/ReportGrievance पोर्टल पर जाकर आय सत्यापन के लिए अनुरोध करते हैं, तो इसके पश्चात नामित लोकल कमेटी (एलसी) इसे सत्यापित करेगी और एफआईडीआर में सत्यापित के रूप में दर्ज करेगी।

### आय प्रमाण पत्र की वैधता

एक बार जारी किया गया आय प्रमाण पत्र (इसके मानक प्रारूप में) जारी होने की तारीख से 31 मार्च (यह तिथि भी शामिल) तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगा। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, यदि उचित प्रक्रिया के बाद भी, यह निष्कर्ष निकालता है कि आय प्रमाण पत्र पर आय का गलत उल्लेख किया गया था या किसी कारणवश एफआईडीआर में गलत तरीके से सत्यापित किया गया था तो आय प्रमाण पत्र अमान्य हो सकता है।

### शिकायत निवारण और सुधार प्रक्रिया

यदि कोई आवेदक एफआईडीआर में निहित अपनी आय से सहमत नहीं है, तो वह पीपीएन पोर्टल के शिकायत मॉडयूल पर पुनः सत्यापन के लिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण कारण अलग से अधिसूचित तंत्र के अनुसार शिकायतों का निपटारा किया जाएगा।

### सामान्य नियम और शर्तें

आय प्रमाण पत्र बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग किया जा सकता है, जहां इसे स्वीकार किया जाता है (अर्थात प्रमाण पत्र स्वीकार करने वाली इकाई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अधीन)। इसलिए प्रमाण पत्र पर इसके उपयोग/प्रयोग्यता प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

इस आदेश की प्रभावी तिथि से, केवल पीपीएन और एफआईडीआर में निहित सत्यापित डाटा के आधार पर नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सरल पोर्टल के माध्यम से जारी आय प्रमाण पत्र ही वैध आय प्रमाण पत्र होंगे।

किसी भी धोखाधड़ी, गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने या किसी अन्य अवैध तरीके से प्राप्त आय प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और उम्मीदवार या आवेदक द्वारा प्राप्त लाभ वापस ले लिया जाएगा और आवेदक को तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने व धोखाधड़ी करने के लिए आपराधिक कार्यवाही सहित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा, अधिकारियों / अधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ मिलीभगत या अन्यथा गलत सत्यापन के लिए भी आपराधिक कार्यवाही सहित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसी घटनाओं में, आय को एफआईडीआर में सत्यापित नहीं के रूप में मार्क किया जाएगा।

कोई भी सरकारी संगठन, जो किसी योजना, लाभ आदि के लिए आय प्रमाण पत्र की भौतिक प्रति स्वीकार करता है, पीपीपी पोर्टल पर उस व्यक्ति जिससे प्रमाण पत्र संबंधित है,की सत्यापित आय की वास्तविक समय स्थिति की जांच कर सकता है।

-संवाद ब्यूरो

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत धार्मिक एवं सामाजिक संस्था बनाने पर अनुसूचित जाति वर्ग की संस्था को प्लॉट की 20 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग-ए को 30, पिछड़ा वर्ग-बी को 40 व सामान्य वर्ग को केवल 50 प्रतिशत हिस्सा देना होगा।

एचएसवीपी ने वर्ष 2020-21 में 2 हजार करोड़ रुपए, 2021-22 में 8 हजार करोड़ रुपए की राशि अर्जित की। मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने बताया वर्ष 2022 में प्राधिकरण ने 10 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य लिया हुआ है।

# पिछड़े वर्ग-ए को मिली राजनीतिक हिस्सेदारी

## 50 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं की रहेगी चौधर

पंचायती राज संस्था के चुनाव में पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए पहले ही 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी तय कर दी गई थी। हरियाणा प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है। चुनाव संभवतः अगले माह संपन्न करा लिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है।

पिछड़े वर्ग-ए के उम्मीदवारों के लिए पंचायती चुनावों में अभी तक आरक्षण का प्रावधान नहीं था। पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पास किया गया।

पिछड़ा वर्ग ए में कुल 71 जातियां हैं। जिन गांवों में इस वर्ग के परिवारों की संख्या ज्यादा है वहां रोटेशन के आधार पर उम्मीदवार चुनाव में भाग ले सकेंगे। यदि किसी गांव में मात्र 2 प्रतिशत भी पिछड़ा वर्ग (ए) की आबादी है तो कम से कम एक पंचायत सदस्य जरूर बनेगा।

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग-ए को पंचायतीराज संस्थाओं में राजनैतिक आरक्षण के संबंध में निर्देश दिए थे। हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग-ए को इसी संबंध में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था। जिसने सैंपल सर्वे करवाया और रिपोर्ट पेश की। कैबिनेट की बैठक में हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2022 लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन किया गया है।

**पंच:** वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों को छोड़कर पिछड़ा वर्ग के लिए ड्रॉ के माध्यम से अलॉट किया जाएगा। प्रत्येक चुनाव में रोटेशन के आधार पर वार्ड आरक्षित किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि पिछड़े वर्ग (ए) की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का दो प्रतिशत या अधिक है।

इस उप-धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत में जहां पिछड़े वर्ग (ए) के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या में कुल वार्डों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक है तो पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षित वार्डों को इतनी बड़ी संख्या तक सीमित कर दिया जाएगा।

**सरपंच:** ब्लॉक में सरपंच की कुल संख्या के आठ प्रतिशत पद पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षित किए जाएंगे। डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक होने पर अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षण के लिए प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की पिछड़ा वर्ग (ए) की उच्चतम जनसंख्या वाली तीन गुना पंचायतों में से ड्रा द्वारा आवंटित किया जाएगा।

**पंचायत समिति:** प्रत्येक पंचायत समिति में पिछड़े वर्ग (ए) के लिए वार्ड आरक्षित होंगे। पंचायत समिति में पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए पंचायत समिति क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के आधे के अनुपात में सदस्य के पद आरक्षित होंगे। यदि आरक्षित पदों की संख्या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों सहित 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। तो उस अवस्था में पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा।

जिला परिषद : जिला परिषद में भी पिछड़े वर्ग(ए) के लिए पद आरक्षित होंगे। जिला परिषद में पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए उनकी जिला परिषद क्षेत्र में उसकी जनसंख्या के आधे के अनुपात में जिला परिषद सदस्य के लिए पद आरक्षित होंगे। यदि आरक्षित पदों की संख्या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों सहित 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी तो उस अवस्था में पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा।

-संवाद ब्यूरो

### दो चरणों में होंगे पंचायत चुनावः आयोग

हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द होंगे। संभवतः अक्टूबर में चुनाव कराने की तैयारी है। ये चुनाव 2 चरणों में होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा होने के बाद चुनाव कराने में कम से कम एक माह का वक्त लगेगा। चुनाव की सारी तैयारी की जा चुकी है। धनपत सिंह ने कहा कि चुनाव कराने के लिए आयोग की ओर से जिला स्तर पर आवश्यक सामग्री भेजी जा चुकी है। जहां बजट की जरूरत थी, वहां बजट भेजा जा चुका है। आयोग के पास करीब 70 हजार ईवीएम हैं, जिनमें से इन चुनावों के लिए लगभग 40 हजार पर्याप्त होंगी। भारत कंपनी की ओर ईवीएम की जांच की जा चुकी है।

# अमृत सरोवर योजना से बदल रही गांवों की तस्वीर

मनोज प्रभाकर

महात्मा गांधी ने कहा था, देश की आर्थिक उन्नति के लिए ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगा तथा गांव में कुटीर उद्योगों पर ध्यान देना होगा ताकि रोजगार के प्रचूर अवसर उपलब्ध हो सकें। गांवों का विकास होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा।

हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में विशेष ध्यान दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के हर भाग में विकास कार्य हो रहे हैं। लोगों का जीवन सहज व सरल हो इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। सरकार की ऑनलाइन सेवाओं ने तो इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। यही वजह है कि लोगों की गांव से शहर की ओर पलायन करने की रफ्तार कम हुई है।

गांवों में पेयजल एवं सिंचाई जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की 'अमृत सरोवर योजना' पर कार्य हो रहा है। इनसे न केवल भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा, गांवों का सौंदर्यीकरण भी होगा।

हरियाणा सरकार ने अमृत सरोवर योजना के तहत अपने तय लक्ष्य से अधिक अमृत सरोवर बनाकर एक और उपलिब्ध हासिल

की है। 15 अगस्त, 2022 तक प्रदेश में 418 अमृत सरोवर बनाये जाने थे, लेकिन सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 557 अमृत सरोवर बनाये जा चुके हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाये जाने हैं।

हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य में और तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि अमृत सरोवर और अन्य सभी तालाबों के कार्यों को तय समय में पूरा किया जाए। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि तालाबों को बचाने और उनके जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन में बेहतर प्रदर्शन कर हरियाणा को देश में अग्रणी राज्य बनाना है।

गौरतलब है कि प्रदेश में कुल 5216 तालाबों के जीर्णोद्धार की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इन तालाबों में से 4811 तालाबों का डिजिटल सर्वे करवा लिया गया है और उसके बाद 3404 की शक्लोसूरत बनाने के लिए कार्य आवंटित कर दिया है। 2737 तालाबों की ड्रॉइंग्स बनाने के बाद अनुमानित लागत तैयार की जा रही है। 268 ड्रॉइंग्स का सत्यापन किया जा रहा है। केवल 399 ड्रॉइंग्स प्रक्रियाधीन है, जिनका कार्य 30 सितंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

5216 तालाबों के लिए ट्रिटिड वॉटर के पुनः उपयोग के लिए मिकाडा द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली हेतु कार्य योजना के अनुसार अभी तक 488 की फीजिबिलिटी चैक करने उपरांत अनुमानों को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। जिन पर कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, अमृत सरोवर योजना और अन्य तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु 1032 कार्यों के अनुमान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 644 कार्यों के लिए 496 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और शेष कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति भी जल्द प्रदान कर दी जाएगी।

बता दें कि हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पीडीएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य में स्थित सभी तालाबों का डाटा एकत्रित किया गया है। सर्वप्रथम प्रदूषित और ओवरफ्लो वाले लगभग 1800 तालाबों को कंस्ट्रक्टिड वेटलैंड तकनीक के माध्यम से उपचारित किया जा रहा है।

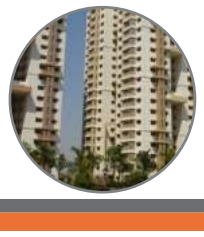

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला व चंडीगढ़ में काम करने वाले कर्मचारियों, पत्रकारों, वकीलों, विधायकों व पूर्व विधायकों के लिए कोऑपरेटिव रूप हाउसिंग सोसासिटी बनाने की स्कीम के लिए मंजूरी दी है।

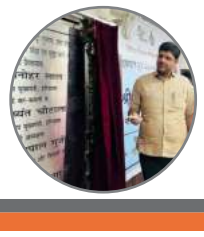

फरीदाबाद को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से 302 करोड़ रुपए की सौगात मिली। इनमें चार विकास योजनाओं का उद्घाटन व छह योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

# केंद्र के सहयोग से और मजबूत होंगी स्वास्थ्य सेवाएं

## प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 110 करोड़ स्वीकृत

हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती लाने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 110 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान इस मिशन के तहत करनाल, पलवल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में इंटीग्रेटेड जिला पब्लिक हेल्थ लैब का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा, जिस पर लगभग 5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा जींद, झज्जर और फरीदाबाद के बी.के. अस्पताल में 50-50 बेड के तीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनाये जाएंगे। जिन पर लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही, राजकीय मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां में लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। हाल ही में स्टेट हैल्थ सोसायटी एनएचएम की बैठक में यह जानकारी दी गई।

**ई-संजीवनी ओपीडी से टेली-परामर्श**

ई-संजीवनी हेल्थ एंड वेलनैस सेंटर टेली-कंस्लटेशन सर्विस के तहत पीजीआईएमआर, चंडीगढ़ में एक हब बनाया गया है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24 घंटे टेली-कंस्लटेशन सर्विस के लिए उपलब्ध है। हेल्थ एंड वेलनैस सेंटर के डॉक्टर मरीजों की बीमारी के संबंध में ऑनलाइन माध्यम से सीधे पीजीआई के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले रहे हैं। हरियाणा की इस पहल की लोकसभा में भी प्रशंसा हुई है। ई-संजीवनी सरकार की राष्ट्रीय टेली-परामर्श सेवाओं के तहत एक ऑनलाइन स्टे होम ओपीडी है जिसे हरियाणा में भी शुरू किया गया है। इस सेवा के तहत लैपटॉप/डेस्कटॉप या एंड्रॉइड स्मार्ट का उपयोग करके कोई भी डॉक्टर से परामर्श ले सकता है। अब तक ई-संजीवनी ओपीडी के माध्यम से 109100 टेली-परामर्श किए जा चुके हैं।

**छह स्पेशलाइज्ड एमसीएच विंग स्थापित**

राज्य में आरएमएनसीएएच + एन सेवाएं प्रदान करने के लिए पंचकूला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल के सिविल अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज, नूंह में एक छत के नीचे छह स्पेशलाइज्ड एमसीएच विंग स्थापित किए जाएंगे। एमसीएच के सभी विंगों के ड्रॉइंग को मंजूरी दे दी गई है। एमसीएच पंचकूला और पानीपत में निर्माण कार्य जारी है। एमसीएच फरीदाबाद के लिए टेंडर प्रक्रिया में है।

**शिशु मृत्यु दर में गिरावट**

प्रदेश में पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला के जिला अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट (एचडीयू) और इंटेसिव केयर यूनिट (आईसीयू) की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। एसआरएस 2020 के अनुसार हरियाणा की शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 28 है, जोकि 2013 में 41 थी। इसमें 13 अंकों की उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। राज्य में केएमसीयू सहित 24 विशेष नवजात देखभाल इकाई (एसएनसीयू), 66 नवजात स्टेबलाइजेशन यूनिट (एनबीएसयू), 318 नवजात शिशु देखभाल कॉर्नर (एनबीसीसी) और 11 पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) कार्यरत हैं।

## 'पोषण माह' को समर्पित सितंबर

# जनभागीदारी से कुपोषण मुक्त होगा हरियाणा

उचित पौष्टिक खान-पान हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी मकसद से प्रतिवर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर मनाया जाता है। पोषण माह महिला एवं स्वास्थ्य, पोषण भी-पढ़ाई भी और जल संरक्षण व जल प्रबंधन तीन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है। वहीं, कुपोषण मुक्त हरियाणा की परिकल्पना के तहत प्रदेश में गांव से लेकर शहर तक जनांदोलन चलाया जा रहा है। 25,962 आंगनवाड़ियों के साथ-साथ पंचायत, पालिका, तहसील से लेकर जिला स्तर पर आयोजन की रफ्तार तेज़ हो चुकी है। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय पोषण मेला आयोजित किया जा रहा है।

एक सितंबर से पांचवें राष्ट्रीय पोषण माह के आगाज के साथ ही प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में अलग-अलग खंडों में प्रतिदिन हजारों छोटे-छोटे आयोजनों के माध्यम से कुपोषण के प्रति आमजन को ज़ागरूक किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने हरियाणा सिविल सचिवालय के आठवें तल स्थित कार्यालय में प्रदेश भर में शुरू हो रहे पोषण माह के लिए संतुलित आहार किट व पोषण कैलेंडर का लोकार्पण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के सामंजस्य के साथ महिला एवं स्वास्थ्य, पोषण भी-पढ़ाई भी और जल संरक्षण व प्रबंधन के लक्ष्य के अनुरूप विशेष कार्य योजना के अनुरूप

पोषण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी ज़रूरी है। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे। गर्भवती महिलाओं के वजन का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। महिलाओं की लगातार मानीटरिंग की जाएगी। एनीमिया के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी आधार पर उनको राशन उपलब्ध कराया जाएगा।

**कमलेश ढांडा, महिला एवं बाल विकास मंत्री, हरियाणा**

अधिक से अधिक जनभागीदारी करवाने पर जोर दिया। राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम के माध्यम से देश मे कुपोषण के खिलाफ़ लड़ाई को तेज करते हुए 67 फीसदी आबादी के पोषण स्तर को बढ़ाने पर ज़ोर दिया है।

**कुपोषित बच्चों को उचित आहार**

फील्ड में जिला परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को 10-10 आंगनवाड़ी केंद्रों पर निजी तौर पर कार्यक्रमों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं मुख्यालय अधिकारी प्रतिदिन आयोजनों की निगरानी करेंगे। कुपोषित बच्चों को उचित आहार देने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। कुपोषण को दूर करने के लिए और मोटे अनाज के प्रति लोगों को ज़ागरूक करने के लिए जगह-जगह ज़ागरूकता रैली निकाली जा रही है। कुपोषण से लड़ने के लिए पंचायत और विकास, पब्लिक हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है।

जिलों में ज़ागरूकता कार्यक्रम

आंगनवाड़ी वर्कर्स घर-घर जाकर लोगों को ज़ागरूक करने के लिए पौष्टिक आहार की जानकारी दे रही है और सभी जिलों में महिला गोष्ठी करवाई जाएंगी। 30 सितंबर तक चलने वाले पोषण माह के दौरान रेसिपी प्रतियोगिता, पौष्टिक थाली प्रतियोगिता, सफाई अभियान, साइकिल रैली, नुक्कड़ नाटक, रागिनी, प्रभात फेरी जैसे प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम सभी जिलों में करवाए जाएंगे। महिला समूहों को भी पोषण माह में भागीदारी के लिए ज़ागरूक किया जाएगा। कुपोषण को दूर करने के लिए कॉलेज, विश्वविद्यालयों की होम साइंस की अध्यापिकाओं को भी पोषण माह से जोड़ा जाएगा।

**हर आंगनवाड़ी में पांच पोषण वाटिका**

पोषण अभियान के तहत प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के दायरे में पांच-पांच पोषण वाटिका बनाई जाएंगी। पोषण वाटिका से उगाई जाने वाली सब्ज़ियां पोषक तत्वों से भरपूर रहेंगी। वाटिका में उगाई जाने वाली हरी सब्ज़ियां, सहजन, करौंदा और नींबू के गुणों के बारे में जनसामान्य को ज़ागरूक किया जाएगा। पोषण वाटिका में रोज़मर्रा उपयोग में आने वाली सब्जी जैविक खाद द्वारा तैयार करने की सरल विधि बताई जाएगी, ताकि लोग कैमिकल युक्त खाद के स्थान पर जैविक खाद से तैयार सब्ज़ियों का सेवन कर स्वस्थ रह सके। पोषण वाटिका तैयार करने में उद्यान विभाग, कृषि विभाग के अधिकारियों का सहयोग लिया जाएगा।

सरकारी कार्यालयों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन व सावर्जनिक स्थानों पर हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 9050891508 प्रदर्शित किया जाएगा।

हरियाणा पुलिस को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा 'स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान आईटी आधारित पहल 'केंद्रीकृत वाहन टोइंग प्रबंधन प्रणाली' के लिए दिया गया है।

## सबका साथ-सबका विकास

# करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गत दिनों शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, परिवहन व ढांचागत विकास की 174 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए। इन परियोजनाओं पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ और सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए प्रदेश को और सशक्त बनाने के संकल्प पर आगे बढ़ रही है। सरकार का ध्येय है कि प्रदेश का कोई हिस्सा विकास परियोजनाओं से अछूता ना रहे। उन्होंने कहा कि विकास के कार्य एक जिले में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में हो रहे हैं। देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण योगदान है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उद्योग आएगा, निवेशक आकर्षित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित होने वाले बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। इस बार के बजट में 34.4 प्रतिशत बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है।

जिन परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए उनमें रैवेन्यू विभाग के 128 करोड़ रुपए के 9 प्रोजेक्ट्स, शिक्षा के 22 करोड़ रुपए के 6 प्रोजेक्ट्स, शिक्षा विभाग के 28 करोड़ की लागत के 7 प्रोजेक्ट्स, उच्च शिक्षा विभाग के 9 करोड़ की लागत के 2 प्रोजेक्ट्स, तकनीकी शिक्षा विभाग के 8 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। वहीं एचवीपीएन, डीएचबीवीएन और यूएचबीवीएन के 375 करोड़ की लागत के 37 प्रोजेक्ट्स, पीडब्ल्यूडी के 439 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाएं, हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 146 करोड़ रुपए की लागत के 2 प्रोजेक्ट्स, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के 101 करोड़ रुपए की लागत के 5 प्रोजेक्ट्स, सिंचाई विभाग के 168 करोड़ रुपए के 22 प्रोजेक्ट्स, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के 6 प्रोजेक्ट्स, स्वास्थ्य विभाग के 291 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट्स, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान और विकास व पंचायत विभाग के एक-एक प्रोजेक्ट्स, विकास और पंचायत (पंचायती राज) के 4 प्रोजेक्ट्स, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का एक, परिवहन विभाग के दो, शहरी स्थानीय निकाय और एचएसआईआईडीसी के दो-दो प्रोजेक्ट्स, एचएसवीपी और कृषि विभाग के एक-एक, कृषि एचएसएएमबी और मेवात विकास प्राधिकरण के तीन प्रोजेक्ट्स शामिल है। इसके साथ ही करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 197 करोड़ की लागत के 11 प्रोजेक्टस शामिल हैं।

चरखी दादरी जिला में रेवेन्यू विभाग द्वारा बनाए जाने वाले नए सचिवालय भवन का शिलान्यास, फतेहाबाद के सेक्टर-9 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 234 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले 200 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल का शिलान्यास, फतेहाबाद में ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा 20 करोड़ रुपए से बनाए गए नए बस स्टैंड का उद्घाटन, हिसार में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के चार सब स्टेशनों का शिलान्यास, सिविल अस्पताल बहादुरगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आईसीयू/एचडीयू के नए भवन, प्रथम तल और ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन, जींद के सिनसर, कर्मगढ़, करसिंधु और रामराई में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 115 करोड़ रुपए की लागत से बने प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन, सफीदों में रेवेन्यू विभाग द्वारा करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से एसडीओ सिविल कॉम्प्लेक्स में प्रशासनिक ब्लॉक (एसडीएम कार्यालय) का उद्घाटन, रैवेन्यू विभाग द्वारा कलायत में करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से बने एसडीओ सिविल कॉपलेक्स का उद्घाटन किया गया।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 37 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास, मारकंडा नदी पर एचएल ब्रिज और गांव बीर मथाना, निर्वाचन क्षेत्र लाडवा में नए स्कूल भवन का उद्घाटन, महेंद्रगढ़ मेआवासीय सुविधा के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलरा बास का उद्घाटन, सतनाली और सहलांग में सरकारी आईटीआई का उद्घाटन, नूंह में पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) द्वारा करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम-अलवर से नई बाईपास सडक़ के निर्माण का शिलान्यास, सीएचसी पुन्हाना में 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एएनएम ट्रेनिंग स्कूल और छात्रावास का उद्घाटन, पलवल के उटावाड़, कलसडा और चैंनसा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्मित पीएचसी का उद्घाटन, 47 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 220 केवी एआईएस सब स्टेशन हरफाली का शिलान्यास, पंचकूला में यूएचबीवीएन के हेड ऑफिस की बिल्डिंग और मोरनी में थंडोग से धार स्कूल तक लिंक रोड का उद्घाटन, पानीपत में 8 स्थानों पर एचबीवीएन के 33 केवी सब स्टेशनों का उद्घाटन, रेवाड़ी में सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 66 करोड़ रुपए की लागत की नहर आधारित जलापूर्ति योजना उद्घाटन, रोहतक में 10 एमएलडी मौजूदा एसटीपी पर 23 करोड़ रुपए की समुदाय आधारित सौर/ग्रिड पावर्ड एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचा परियोजना का शिलान्यास, सोनीपत के गांव जुआँ में नए बने आईटीआई भवन का उद्घाटन, यमुनानगर के छपड़ में बने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, जगाधरी के सरस्वती नगर में बने बस स्टैंड और नचरौन में आईटीआई का उद्घाटन किया।

### विकास कार्यों की निगरानी के लिए क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ संभावित भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए • लिटी कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की घोषणा की है। यह अथॉरिटी समय-समय पर प्रोजेक्ट्स की चैकिंग करेगी और अगर कोई खामी पाई जाती है तो दोषी अधिकारियों को पकड़ेगी और उन्हें सजा दिलाने का काम करेगी।

सरकार ने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है जिससे सरकारी प्रोजेक्टस के आवंटन में पारदर्शी बढ़ेगी। अब निर्माण कार्य के टेंडर ऑनलाइन होंगे। इसके माध्यम से कांट्रेक्टर्स अपनी कोटेशन भर सकेंगे और उन्हें अधिकारियों के चक्क र नहीं काटने पड़ेगे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से भी इसमें सहयोग का आह्वान किया और कहा कि हम ऐसा तंत्र विकसित करेंगे जिसमें जनता प्रोजेक्ट्स की • लिटी, भ्रष्टाचार, मिक्सिंग या सब स्टैंडर्ड की जानकारी एक पोर्टल पर देगी। उस जानकारी की प्रारंभिक जांच की जाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो सरकारी नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी, आवश्यकता पड़ी तो उस प्रोजेक्ट को दोबारा बनाया जाएगा।

हरियाणा के 29,704 कृषि नलकूप उपभोक्ताओं ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिनमें से दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 20,118 बिजली के कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में आठ नए उपमंडल बनाने की घोषणा की है। इनमें बवानीखेड़ा, मानेसर, जुलाना, नीलोखेड़ी, नांगल चौधरी, इसराना, कलानौर और छछरौली शामिल हैं।

# पर्यटन से बढ़ते रोज़गार के अवसर

संगीता शर्मा

पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो विभिन्न संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है। रोज़गार के द्वार सृजित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी मकसद से हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने कालका से कलेसर तक पर्यटन हब विकसित करने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, मोरनी में एडवेंचर स्पोर्ट्स, टूरिज्म सर्किट रूट, माउंटेन ट्रेकिंग, बाइकिंग और पैराग्लाइडिंग सुविधाओं को विकसित किया है। 'होम स्टे स्कीम-2021' से जहां लोग हरियाणा के गांवों, कला व संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं, वहीं छोटे किसानों के लिए आमदनी का साधन भी बन रहे हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले और कुरुक्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव ने राज्य की कला, संस्कृति व पर्यटन की दुनिया में अपनी पहचान कायम की है। प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए पिंजौर में फिल्म सिटी विकसित करने की दिशा में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं।

### सांस्कृतिक विरासत

हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में तीर्थों के रख-रखाव के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इसके द्वारा आस-पास के 48 कोस की परिधि के 164 तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की इच्छा जताई थी। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 2016 से हरियाणा सरकार अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मना रही है। महेंद्रगढ़-नारनौल सर्किट के अंतर्गत महेंद्रगढ़ किले के विकास के लिए व रानी महल, बावड़ी के आंतरिक व बाहरी क्षेत्र के विकास के लिए व माधोगढ़ किले को छोड़कर किले के आस-पास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए 29.61 करोड़ की राशि की परियोजना पर कार्य शुरू किया गया।

### एडवेंचर गतिविधियों को बढ़ावाः

पंचकूला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए टिक्करताल, मोरनी हिल्स को साहसिक खेल गतिविधियों जैसे पैरासेलिंग, पैरामोटर और जैट स्कूटर जैसी ऐरो स्पोर्ट्स और वॉटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियां व्यावसायिक रूप से चालू की गई। इसके साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स के ज़रिए हरियाणा में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा। हरियाणा में एडवेंचर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मोरनी में 'सरदार मिल्खा सिंह क्लब' की स्थापना की गई है जिससे इस क्षेत्र में कई गतिविधियां संचालित की जा रही है।

नाडा साहिब गुरुद्वारा व माता मंसा देवी मंदिर, पंचकूला के विकास हेतु भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा 49.51 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई और परियोजना पर निर्माण कार्य जारी है। गुरुग्राम में अरावली पर्वत शृंखला में ट्रैकिंग तथा जंगल सफारी बनाई जाएगी। इसके लिए परियोजना तैयार करने को अधिकारियों को कहा गया है।

### तीर्थयात्री वित्तीय सहायता :

हरियाणा सरकार द्वारा सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा हेतू 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति/तीर्थ-यात्री, कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतू 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति/तीर्थयात्री और गुरु दर्शन योजना के लिए श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा (नंदेड), श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब तथा श्री पटना साहिब हेतू 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति/तीर्थयात्री वित्तीय सहायता दी जा रही है।

## होम स्टे से ग्रामीण संस्कृति का परिचय

शहरों की भाग-दौड़ व तनावपूर्ण ज़िंदगी से दूर व्यक्ति छुट्टियों में कहीं शांत व ग्रामीण माहौल में दिन व्यतीत करना चाहता है। ये पल उन्हें हरियाणवी संस्कृति व परिवेश से जोड़े रखने मददगार साबित हो रहे हैं। ऐसे में हरियाणा पर्यटन विभाग की 'होम स्टे' योजना सफल साबित हो रही है। फार्म टूरिज्म को नये रूप में ढालते हुए 'होम स्टे स्कीम-2021' की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत विशेषकर छोटे किसान पर्यटकों और मेहमानों को व्यावसायिक आधार पर कमरों/आवास की पेशकश कर सकते हैं।

### पारंपरिक खेलों का प्रबंध

यहां बच्चों के लिए गिल्ली-डंडा, पिठ्ठू, कंचा गोली, गुलाल, कबड्डी, खो-खो और कई तरह की गतिविधियां है, जो उन्हें स्कूल के दिनों वापिस लौटा देती है और अंतहीन खुशी महसूस करवाती है। वृद्ध लोग भी यहां आकर अपनी यादों को ताज़ा करते हैं। चरखा, चक्की, पीसना, माखन और घी बनाना जैसी कई अन्य गतिविधियां लोगों को हमारे बदले हुए परिवेश को भी दिखाकर जीवन के 50 साल पीछे ले जाती है। जुताई, बुवाई, फसल कटाई, अनाज पछारना, बायोगैस प्लांट, मुर्राह दुहना, हरियाणा गाय के सफेद बैल शो आदि देखने लायक हैं जो शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं।

### ग्रामीण परिवेश का आनंद

यहां गन्ना रोपण, खाना, गुड़ बनाना और गरमागरम गुड़ खाना आदि देखने और आनंद के लिए हैं। हरियाणवी सांस्कृतिक गीत, ग्राम शो, कठपुतली शो, रागिनी, पोशाक, घाघरा चोली, गहने और अनगिनत चीजें रोमांचक पर्यटन के लिए उपलब्ध हैं। ऊंट की सवारी, बैल की सवारी, ट्रैक्टर चलाना, मिट्टी का स्नान, ट्यूबवैल स्नान, सब्ज़ी स्वयं खाना-बनाना वास्तव में सभी को अंतहीन आनंद दे रहे हैं।

कुरुक्षेत्र को हम हरियाणा की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी कह सकते हैं। इसे महापर्यटन स्थल बनाने पर कार्य किया जा रहा है। कालका से कलेसर तक को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना पहले ही बना चुके हैं जिसे चरणबद्ध तरीके से मूर्तरूप दिया जा रहा है। मोरनी क्षेत्र को तीन राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार, यहां पर मोरनी के टिक्कर ताल में एअर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स व साहसिक खेलों की गतिविधियां शुरू की गई है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ युवाओं के लिए रोज़गार का साधन खुल रहे हैं। पिंजौर में 60 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। साथ ही पंचकूला को खेल, पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्मिक व आधारभूत संरचना की दृष्टि के विकसित किया गया है। गुरुग्राम में जंगल सफारी विकसित होने से एक ओर जहां इस पर्वत शृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों से यहां काफी संख्या में लोग पर्यटन के लिए आएंगे जिससे स्थानीय लोगों के लिए बहुत सारे रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। आस-पास के गांवों में ग्रामीणों को होम स्टे पॉलिसी के तहत लाभ होगा।

**मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा**

## 20 हजार एकड़ में मक्का की खेती का लक्ष्य

हरियाणा में मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान केंद्र कार्य कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 500 एकड़ में प्रदर्शन खेती फ़ार्म की योजना तैयार की गई है। किसानों का रुझान मक्का की ओर बढ़े इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। किसानों को किसान उत्पादन समूह के माध्यम से उद्योग से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला या करनाल में सितंबर माह के तीसरे सप्ताह में मक्का दिवस भी मनाया जाएगा।

भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों को जानकारी दी गई कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही सजग हैं। उन्होंने 'मेरा पानी-मेरी विरासत' नाम की एक अनूठी योजना लागू की है जिसके तहत धान की फसल के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 7 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बाजरा बाहुल्य जिले नामतः नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी में भी मक्का की फसल के प्रति किसानों को प्रेरित करने के लिए परिषद कार्य करे। सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। परिषद ने पंजाब में मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई साइलो प्लांट बनाए हैं जहां से पशु चारा पैक कर दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। परिषद हरियाणा में भी साइलो पर काम करने की योजना तैयार कर रहा है।

हरियाणा में मक्का की खेती वाले जिलों में सोनीपत, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल शामिल हैं। हालांकि सिरसा, भिवानी, पानीपत, रोहतक, करनाल व चरखी दादरी के कुछ क्षेत्रों में भी मक्का की खेती की जाती है। खरीफ सीजन 2022-23 के लिए लगभग 20,000 एकड़ क्षेत्र मक्का की खेती के अधीन लाने का लक्ष्य रखा गया है। औसतन उत्पादन 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ रहता है तथा 25,000 मीट्रिक टन मक्का के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत में मक्का का उपयोग बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न व अन्य आहार के रूप में किया जाता है। पशु आहार में भी मक्का का उपयोग होता है। स्टार्च उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। सोनीपत जिले का मनोली गांव तो बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती के लिए जाना जाता है। वर्ष 2022 -23 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1962 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। हरियाणा में खरीफ मक्का की बुआई आमतौर पर 15 जून से 20 जुलाई के बीच होती है तथा कटाई का समय 10 सितंबर से 31 अक्टूबर तक रहता है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि फसल च' में बदलाव जल संरक्षण के लिए दिन-प्रतिदिन समय की आवश्यकता बनता जा रहा है। कम पानी से पकने वाली फसलों पर कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। किसानों को भी अधिक से अधिक फसल विविधीकरण की ओर जाना होगा। प्रदेश में मक्का के अधीन क्षेत्र को बढ़ाने की योजना तैयार की जा रही है।

हरियाणा सरकार फसल अवशेषों को जलाने पर रोक लगाने के लिए स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों के माध्यम से ज़ागरूकता अभियान चलाएगी। फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले नुकसान से अवगत करवाएंगे।

प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में फर्स्ट-एड की ट्रेनिंग के लिए एक विंग स्थापित की जाएगी, जिसके तहत रेडक्रॉस द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग इन विंग के माध्यम से प्रदान होगी।

# अध्यापक दिवस पर 93 अध्यापकों को पुरस्कार

## 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कराएगी सरकार

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2020 व 2021 के प्रदेश के 93 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जांच के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना 'सेहत' का शुभारंभ भी किया।

शिक्षक दिवस पर सम्मानित हुये शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने एक शिक्षक के साथ-साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर कार्य किया है। शिक्षित एवं स्वस्थ बच्चे देश का भविष्य हैं। देश के इस भावी कर्णधार भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आज यहां से आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना 'सेहत' शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत आगामी शैक्षणिक सत्र से साल में दो बार 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। जांच में एकत्रित किए गए डेटा को ई-उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी स्थान पर बच्चे का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध होगा।

शिक्षामंत्री कंवर पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हरियाणा देश का ही नहीं संभवत विश्व का पहला प्रदेश है जहां 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों और शिक्षकों को पांच लाख टैब निशुल्क प्रदान किये गये। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे प्रतिभावान होने के बावजूद संसाधनों के अभाव में पीछे रह जाते है। उन्हें सरकार द्वारा संसाधन उपलब्ध करवाये गये हैं, जिसके परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे।

## अंजू दहिया ने खेल-खेल में पढ़ाया रसायन विज्ञान

अक्सर विद्यार्थी रसायन विज्ञान विषय से घबराते हैं। इस कठिन विषय को सोनीपत के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बड़वासनी (सोनीपत) की रसायन विज्ञान की प्राध्यापिका अंजू दहिया ने कविता व खेल गतिविधियों के साथ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से पढ़ाया। जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। इस विषय को इतना अधिक रोचक बनाया कि उनके स्कूल में विज्ञान विषय में विद्यार्थियों का दाखिला बढ़ गया। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अतुलनीय कार्यों को देखते हुए अंजू दहिया को दिल्ली में शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च पुरस्कार 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार' से सम्मानित किया। तबादला नीति में प्राध्यापिका अंजू दहिया का गांव खांडा में स्थानांतरण हुआ है। अंजू दहिया ने कहा कि भले स्कूल से तबादला हो गया हो, विद्यार्थियों को जब भी ज़रूरत होगी, तो वह मदद के लिए तैयार है।

अंजू दहिया ने कहा कि उनमें हमेशा कुछ नया करने की इच्छा जागृत होती थी। शिक्षा के क्षेत्र में आकर विद्यार्थियों की समस्या को समझा। जिसका समाधान करने के लिए विद्यार्थियों के साथ समय बातचीत कर विषय को सरल बनाने के लिए उनके साथ समय बिताया। रसायन शास्त्र विषय को कविता व खेल गतिविधियों में बांटा। सोनीपत के सेक्टर-23 निवासी शिक्षिका अंजू दहिया ने वर्ष 2013 में शिक्षा विभाग ने पीजीटी रसायन विज्ञान के पद पर ज्वाइन किया था। वर्ष 2014 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बड़वासनी में तबादला हुआ। इसके बाद से अंजू दहिया इसी स्कूल में कार्यरत हैं। अंजू दहिया का कहना है कि वह बचपन से पढ़ाई के साथ नए-नए प्रयोग करती रहती थी, जो कि शिक्षिका बनने में प्रयोग में लाया। इसी की बदौलत मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाज़ा गया है।

अंजू ने पर्वतारोही का प्रशिक्षण लिया, विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर लेकर जाने से पहले प्रशिक्षण देती हैं। विशेष बच्चों के साथ शैक्षिक भ्रमण पर जाती और उन्हें वहां के बारे में बताती हैं। एलटीसी राशि स्कूल में सुविधाएं बढ़ाने पर ही खर्च की। ग्रामीणों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल में प्रदर्शनी व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की प्राध्यापिका अंजू दहिया ने विदेश में भी प्रचार-प्रसार किया है। उन्होंने उज्बेकिस्तान में 15 दिन तक रहकर वहां के लोगों को भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में प्रेरित किया।

# नई शिक्षा नीति से खुलेंगे रोज़गार के नए आयाम

आजादी के समय मैकाले की वह शिक्षा पद्धति 'तीन आर' राइटिंग, रीडिंग व अरिथमेटिक पर केन्द्रित थी, जो एक नागरिक का संपूर्ण विकास करने वाली नहीं थी। आज 21वीं सदी में आजादी के 75 साल के बाद देश को एक ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जिससे युवा पीढ़ी शिक्षित तो बने ही उसके साथ ही उसमें राष्ट्रीयता की भावना भी पैदा हो। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास है कि हरियाणा जिस प्रकार खेलों में निपुण है, उसी प्रकार शिक्षा में भी अग्रणी बने। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों के साथ सशक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए आधारभूत ढांचा पहले ही तैयार किया जा रहा है। इसके बलबूते नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू की जाएगी। हालांकि इसको लागू करने की समयावधि 2030 तक है, लेकिन हरियाणा इस लक्ष्य को पांच वर्ष पहले ही हासिल कर लेगा।

हरियाणा सरकार स्कूलों में ड्राप आउट रेट कम करके प्रत्येक बच्चे को ट्रैक करेगी इसके लिए शुरू की गई परिवार पहचान पत्र योजना के तहत पंजीकृत हर परिवार के सदस्यों का डाटा विश्लेषण किया जाएगा, ताकि प्रत्येक बच्चे को ट्रैक किया जा सके और किसी कारणवश स्कूल में ना आने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया जा सके।

**स्कूलों में कौशल विकास शिक्षाः** नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य छठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा देना है। हरियाणा में स्कूलों में ही बच्चों को विभिन्न कौशलों में निपुण बनाने की व्यवस्था की है।

कौशल विकास के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय खोला गया है। इस विश्वविद्यालय ने उद्योगों के साथ सुदृढ़ संबंध बनाए हैं और सैंकड़ों एमओयू किये हैं। विश्वविद्यालय में 34 डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर कार्य' म चलाए जा रहे हैं। लघु अवधि व नियमित पाठ्यक्रमों के माध्यम से 4,755 छात्र प्रशिक्षित किये गये हैं। बदलते माहौल के अनुसार इस विश्वविद्यालय द्वारा कई नए कोर्सिज की पहचान की गई है। इनमें 71,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है।

**विद्यार्थियों के पासपोर्ट निःशुल्कः** भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों तथा विदेश में रोजगार के अवसरों से अवगत कराने हेतु महाविद्यालयों में एक नई महत्वाकांक्षी योजना पासपोर्ट सहायता शुरू की गई है, जिसके तहत अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट निःशुल्क बनाए जा रहे हैं।

**ऑनलाइन कोचिंगः** 50 हजार मेधावी विद्यार्थियों को ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से कोचिंग देने के लिए एम -3 एम फाउंडेशन के साथ भी एम.ओ.यू. किया गया है। इस कार्य' म में प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले युवाओं को कोचिंग देने के साथ-साथ हर सप्ताह उनकी तैयारी की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

**गुरुकुल के विद्यार्थियों को मददः** गुरुकुल को सरकार की ओर से विद्यार्थियों के सहयोग में मिलने वाली सालाना आर्थिक सहायता को दोगुना करते हुए कहा कि गुरुकुल की सहायता के लिए अब 100 विद्यार्थियों तक के गुरुकुल को 1.5 लाख के स्थान पर 3 लाख रुपए, 200 विद्यार्थियों तक के गुरुकुल को 2.5 लाख के स्थान पर अब 5 लाख रुपए और 300 विद्यार्थियों तक के गुरुकुल को 3.5 लाख रुपए के स्थान पर अब 7 लाख रुपए की सालाना सहायता दी जाएगी।

### पहले से किये गये प्रयास

- नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रदेश में 4,000 प्लेवे स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि नई शिक्षा नीति में निहित तीन साल की आयु से बच्चे की शिक्षा आरंभ की जा सके। अब तक 1135 स्कूल खोले जा चुके हैं।
- निजी स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं और अंग्रेजी में शिक्षा देने के लिए 113 नये संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 137 हो गई है। साथ ही, 1418 विद्यालय इंग्लिश मीडियम बैग फ्री स्कूल बनाये जा रहे हैं।
- नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक करना है। इस दिशा में भी हरियाणा प्रदेश काफी आगे है। हमारे यहां लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 32 प्रतिशत है।
- प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किये जा रहे हैं, जिनमें नन्हे बच्चे की केजी कक्षा से युवा विद्यार्थी की पीजी कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रारंभ में ऐसे चार विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था की जा रही है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने तो इसी सत्र अर्थात 2021-22 से केजी से पीजी स्कीम के तहत दाखिलों की तैयारी शुरू कर दी है।
- सरकार ने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। स्कूलों में एन.एस.क्यू.एफ, कॉलेजों में 'पहल योजना' विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ एम.ओ.यू. जैसे कारगर कदम उठाये गये हैं।
- हरियाणा एफएलएन मिशन और सुपर-100 की तर्ज पर कक्षा 9 वीं और 10 वीं के होनहार विद्यार्थियों के लिए बुनियाद कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया है।

शिक्षा के लिए सबसे पहले पर्याप्त आधारभूत ढांचा होना बहुत जरूरी है। इस दिशा में हरियाणा में न केवल पर्याप्त स्कूल कॉलेज हैं, बल्कि विभिन्न विषयों की विशेषज्ञता से युक्त विश्वविद्यालय व विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान भी हैं। राज्य में हर विद्यार्थी के घर से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर एक स्कूल अवश्य है। इसी प्रकार हर 20 किलोमीटर की परिधि में एक कॉलेज उपलब्ध है।

**-मुख्यमंत्री मनोहर लाल**

**-मनोज प्रभाकर**

रक्तदान के संबंध में एक पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर रेडक्रॉस सोसाइटी या अन्य संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले ब्लड डोनेशन कैंपों की जानकारी दर्ज की जाएगी।

राज्य सरकार ने सामाजिक कार्यों में सेवाभाव से योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 'समर्पण पोर्टल' विकसित किया है, जिस पर लगभग 5 हजार वॉलंटियर्स ने अपना पंजीकरण करवाया है।

# धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का निर्वहन आवश्यक

## कुरुक्षेत्र में आचार्य श्री प्रभुपाद का 150वां जन्मोत्सव कार्यक्रम

सनातनी धर्म परंपराएं हमारे मठों और धार्मिक संस्थाओं के योगदान से निरंतर आगे बढ़ रही हैं। इतिहास पर नजर डालें तो हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए कितने ही आक्रमण किए हुए लेकिन हमारी आस्था की गहरी जड़ों की वजह से हमारे मूल्यों पर खरोंच तक नहीं आई। हिंदू धर्म और संस्कृति आज भी ऐसी की ऐसी है। सनातन धर्म की अविरल धारा न रुकी है, न रुकेगी और न इसे कोई रोक पाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के गौड़ीय मठ में आयोजित आचार्य श्री प्रभुपाद के 150वें जन्मोत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हमारे मठ, धर्म और संस्कृति के केंद्र ही नहीं बल्कि हमारी धार्मिक विरासत भी यहीं विराजमान है। मठों से केवल धर्म का प्रचार-प्रसार नहीं, मानवता के संदेश का संचार भी होता है। मठ सनातन संस्कृति का केंद्र हैं। मानव कल्याण के लिए इन्हें स्थापित किये गए।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बहुत सी समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक गलियारे से निकल सकता है। आज समाज को महापुरुषों की शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य कभी-कभी ऐसे चौराहे पर खड़ा हो जाता है, जहां से जीवन की दिशा नहीं मिलती। लेकिन पग-पग पर आने वाली बाधाओं का हल महापुरुषों के जीवन से मिल जाता है। मुख्यमंत्री ने सभी धार्मिक विभूतियों से निवेदन किया कि वे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़े। युवा अपनी संस्कृति के वाहक बने । आने वाली पीढ़ियां न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ें। हमें आदिकाल से चली आ रही मान्यताओं को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। संत-महापुरुषों के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाएं और उनका जीवन में भी अनुसरण करें।

### भारत संत महात्माओं की धरती

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत संत-महात्माओं व पीर-पैगम्बरों की भूमि है। यहां कितने संप्रदाय और भाषाएं हैं, फिर भी हम एक हैं। हिंदू धर्म वह धर्म है, जिसे लोगों ने अपनी आस्था और विश्वास से माना है। हमने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। किसी की आस्था को नहीं झुकाया। हमने हमेशा कहा है हम भी ठीक हैं और आप भी ठीक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व में शायद ही ऐसा देश हो जिसमें विभिन्न विचारधारा के लोग इतने लंबे समय तक सम्माहित होकर अलग पहचान बनाए रखने का उदाहरण प्रस्तुत करते हों। इसका श्रेय उन ऋषि-मुनियों को जाता है, जिन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण के लिए लगा दिया। आचार्य श्री प्रभुपाद भी उन्हीं में से एक हैं।

### संत-महापुरुष विचार प्रसार योजना

देश के संत-महात्माओं ने भूली-भटकी मानवता को रास्ता दिखाया है। ऐसी विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेदारी हम सब की है। हरियाणा सरकार ने संत महापुरुषों के विचारों का प्रचार-प्रसार करने के लिए संत-महापुरुष विचार प्रसार योजना शुरू की है। इसका मकसद संतों के विचार नई पीढ़ियों को मिले। इसके माध्यम से संतो के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। कबीरदास, महर्षि वाल्मीकि, गुरु नानक, गुरु तेगबहादुर जैसे संतों की जयंतियों को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है।

### सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

सांस्कृतिक विरासत संरक्षण व कुरुक्षेत्र में तीर्थों के रख-रखाव के लिए विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इसके द्वारा आसपास के 48 कोस की परिधि के 164 तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की इच्छा जताई थी। प्रधानमंत्री के मार्ग दर्शन में 2016 से हरियाणा सरकार अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मना रही है। गीता जयंती को विदेशों में भी मनाया जा रहा है। 2019 में मॉरिशियस और लंदन में गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र को हम हरियाणा की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी कह सकते हैं।

### 1918 में स्थापित हुआ गौड़ीय मठ

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आचार्य श्री प्रभुपाद ने 1918 में गौड़ीय मठ की स्थापना की। चैतन्य प्रभु द्वारा वैष्णव वाद के सिद्धांत का पालन करते हुए प्राचीन भारत में प्रचलित वर्ण आश्रम धर्म को एक सच्चे वैज्ञानिक और आस्तिक आधार पर प्रस्तुत किया। उन्होंने सनातन धर्म में उपजी विभिन्न भ्रांतियों को खत्म किया था। उन्होंने देश-विदेश में मंदिर के साथ-साथ 64 मठों की स्थापना की। बंगाली, संस्कृत, उड़िया जैसी विभिन्न भाषाओं में अखबार व पत्रिकाएं प्रकाशित कीं। श्री प्रभुपाद ही हरे कृष्ण आंदोलन के सूत्रधार थे। वर्ष 1933 में उन्होंने सनातन धर्म के प्रचारकों को यूरोप भेजा था।

**-सवाद ब्यूरो**

---

**सुण छबीले बोल रसीले**

# सीएम विंडो का कमाल

- रसीले भाई राम-राम
- राम-राम भाई तेरी दो बै राम-राम।
- आज यो दो बै राम-रमी किस बात की ली?
- आज्या बताऊं, पहल्यां होक्का भरल्या।
- होक्का तो भरल्याऊंगा, पर पहल्यां बता तो सही, तनै के पाग्या।
- न्यू होई। बाहरणै वो थोड़ी जगहां बणाई सै। उड़े खातिर बिजली का कनैक्सन चाहिए था। छोरा रमलू बिजली के दफ्तर में जाकै फाइल त्यार करवा आया। फाइल ऑनलाइन जमा होणी थी। उसनै फाइल में आधार कार्ड वगैरह सारे कागजात पूरे कर दिये। सारा काम पूरा होए पाछै फाइल पै एक अफसर के दस्तखत होणे थे। वो अफसर सीट पै कम पावै था। पावै तो दस्तख्त करण तैं मना कर देता।

-क्यूं भाई दस्तखतां नै मना क्यूं करै था?

- बोलता, पहल्या लाइनमैन करैगा, फेर वो करैगा।

-आच्छा फेर?

- फेर वो लाइनमैन टोया। लाइनमैन बोल्या, मैं साइन कोन्या करूं, यू मेरा काम कोन्या। कदे कह, क्लर्क तैं मिलल्यो, कदै कहै जेई साहब तैं मिलल्यो। कोए राह कोन्या देवै। नए कनेक्सन की फीस भी जमा करवा दी थी।

- आच्छा फेर के होया?

- तीन-चार दिन ताहीं चक्कर कटा दिए। छोरे रमलू नै के कर्‌या। इसकी शिकायत सीएम विंडो पै करवा दी।

- आच्छा रै, इसी-इसी शिकायत भी सीएम विंडो पै होज्या सैं?

- सुण तो सही, आगले ए दिन महकमे के दो कर्मचारी म्हारे घरां आगे। मेरे तैं पूछण लागे, बाबूजी आपनै बिजली के कनेक्सन खातिर एप्लीकेशन देणी सै। ल्याओ, वो फाइल हामनै दे द्यो हाम जमा करवा देंगे।

- मनैं अंदाजा लगा लिया अक सीएम विंडो का असर होग्या।

- आच्छा फेर के होया?

- फेर के होणा था, मनैं कह दिया, अक हां भाई हामनै बिजली का कनेक्शन लेणा सै। फाइल भी त्यार करा राखी सै। पर महकमे आल्यां नै म्हारे ताहीं राह ए कोन्या दिया। छोरे नै सीएम विंडो पर आपणी बात कह दी। ईब थाम आगे।

रसीले भाई मनैं भी उन महकमे आल्यां तैं कह दिया अक आज हामनै टैम कोन्या, तड़कै आइयो। न्यू सुणकै वे परेशान होगे। और चले गए। तड़कै फेर आवैंगे।

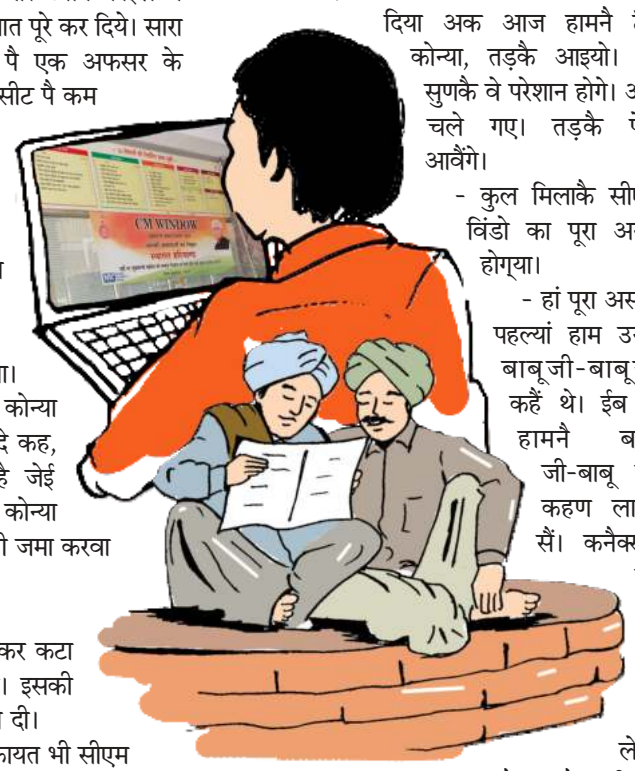

- कुल मिलाकै सीएम विंडो का पूरा असर होग्या।

- हां पूरा असर। पहल्यां हाम उननै बाबूजी-बाबूजी कहैं थे। ईब वे हामनै बाबू जी-बाबू जी कहण लागरे सैं। कनैक्सन तो लेणा सै, तड़कै नहीं तो परसों ले लेंगे, पर पहल्यां इन कर्मचारियां का मजा तो ले लें। इन कर्मचारियां की नीयत और देही इतणी हराम होरी सै अक सीधे हाथ पायां तो काम करकै कतई राजी कोन्या।

- हां भाई गंडा दाब में ए रस देवै सै। इस राज में यू सुख तो सै, अक ऑनलाइन शिकायत करते ही कार्यवाही होज्या सै। पाछले म्हीने मनैं भी पीणे के पाणी की शिकायत टोल फ्री नंबर पै करी थी। कई दिन तैं पाणी कोन्या आवै था।

-आच्छा रै छबीले, थारे कान्या भी यो समस्या सै? थाम तो यूं ए ना डूबा में रहो सो।

- तो भाई शिकायत करणे के आगले दिन दो फोन आए। पहल्यां एक मैडम बोली, उसनै पूछी अक पीणे के पाणी की के समस्या सै। फेर कुछ देर पाछै महकमे के एक जेई का फोन आया। उसनै भी समस्या के बारे में बातचीत करी। आगले दिन टोंटी में पाणी आग्या। इतणा ए नहीं। उस जेई नै और उस मैडम नै तीसरे दिन फोन करकै पूछ्या अक थारे मोहल्ले में पाणी की सप्लाई आगी या नहीं आगी।

- मनैं बता दिया, भाई पाणी आग्या और थारा बोहत-बोहत धन्यवाद।

- रसीले, सरकार और सिस्टम तो ठीक सै। पर काम करणिये निरभाग सैं। काम करकै कतई राजी कोन्या। दस्तख्त करण में भी मरोड़ दिखावैं सैं।

- और सुण भाई, पड़ौस में एक छोरा सै दीक्षू, वो सरकारी नौकरी लाग्या सै। वो और उसका बाबू एक एफीडेविट बणवाण तहसील में चले गए। एफीडेविट तैयार करवाया तो तहसीलदार साफ नाटग्या, अक साइन कोन्या करूं। बोल्या सरकार नै सेल्फ अटेस्टिड की मंजूरी दे राखी सै। आपणे साइन करो और चलाओ। जबकि स्वास्थ्य विभाग नै न्यू लिख राखी थी अक मजिस्टेट के साइन जरुरी सैं। उननै तहसीलदार तैं कई बार रिक्वेस्ट करी और सिफारिश कराई जिब जाकै उसनै साइन करे। और सुण तहसीलदार नै साइन कर दिए तो उसका पीए उसपै मोहर मारण तैं मना करग्या, आंख काढ़कै बोल्यां, कौन्या करता, लंच होग्या। हाथ पां जोड़कै उस धोरै मोहर लगवाई। तो बता इसमें सीएम और पीएम के करैगा ? भला हो इस सरकार का अक ऑनलाइन शिकायतां पै फोरन कार्रवाही होज्या सै।

**-मनोज प्रभाकर**

---

# जय-जय हरियाणा

धन - धन्य भरी ये धरती, दूध-दही का है भंडार,
इसके पनघट, इसके अंचल, ग्राम-ग्राम में हरियाली ।
जय हरियाणा, जय-जय हरियाणा
गूंजी थी कान्हा की बंसी, और गूंजा था पांचजन्य भी
विराट रूप की धरा साक्षी, सरस्वती सभ्यता वैदिक वाली।
जय हरियाणा, जय-जय हरियाणा
शीश हथेली पर रखते हैं , हरियाणे के बांके छोरे ।
पानीपत में राष्ट्रधर्म की शमशीरें, चमकी थीं हिम्मत वाली।
जय हरियाणा, जय-जय हरियाणा
सरहदों पर पहरा देते, इसके भीम, कर्ण और अर्जुन
इसकी मुर्राह छैल छबीली , इसके अल्हड हाली-पाली
जय हरियाणा, जय-जय हरियाणा
सूरदास की जन्म स्थली और च्यवन ऋषि की तपो भूमि है ।
नृत्य, रागिनी, सांग विधा और लोककला की छवि निराली ।
जय हरियाणा, जय-जय हरियाणा
खेलों में सोना बरसायें, हरियाणे के छोरा-छोरी ।
योग, व्यायाम, खेल नीति से, देश की निखरी छवि निराली ।
जय हरियाणा, जय-जय हरियाणा
जन जन देश प्रेम से प्रेरित, कण-कण इसका तीरथ है ।
ग्राम-ग्राम विकास छटा और घर-घर में खुशहाली ।
जय हरियाणा, जय-जय हरियाणा

**धीरा खंडेलवाल**

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com